और साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को मिलाकर शताब्दी के अंत तक लक्षित क्षेत्रों में शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए लक्षित कार्यक्रम के सहभागी क्रियान्वयन की परिकल्पना के माध्यम से उपयुक्त कार्यनीति के साथ एक समेकित ढंग से शहरी गरीबी के मूल कारणों पर प्रहार करना है। नये कर्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैः (क) सामाजिक क्षेत्रक लक्ष्यों की प्रभावी उपलब्धि, (ख) सामुदायिक प्राधिकार (ग) सतत् समर्थन प्रणाली के माध्यम से कवरेज, (घ) रोजगार सृजन तथा कौशल उन्नयन, और (ड) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुधार और पर्यावरणीय सुधार।

कार्यक्रम के प्रमुख संघटक हैः

(क) सूक्ष्म उद्यमों और कौशल विकास की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार, (ख) बुनियादी भौतिक सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार, (ग) आश्रय उन्नयन (घ) सामुदायिक संगठन और प्राधिकार (ड) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) को सुदृढ़ीकरण, (च) राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि (एनयूपीईएफ) की स्थापना, (छ) शहरी डाटाबेस का विकास और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (ज) गैर सरकारी संगठनों का सहयोग।

यह कार्यक्रम 50000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी II नगरों में जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 345 है कि लिए लागू होगा। इस स्कीम का विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमांऊ क्षेत्र के 72 जिला नगरों मे किया गया है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) 2 अक्टूबर, 1993 को आरम्भ की गई थी। पीएमआरवाई इस अमय पूरे देश में 18 से 35 वर्ष की उमर के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए कार्यान्वित की जा रही है (जो कि हाई स्कूल उत्तीर्ण अथवा अनुतीर्ण आई टी आई उत्तीर्ण अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स किए हो) और जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी से अधिक न हो; अर्थात् 24,000 रुपये से अधिक न हो।

इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रु० तक की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। उधार लेने वाले व्यक्ति से परियोजना की कुल लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होती है और उसे परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में जमा कराना पड़ता है। शेष 95 प्रतिशत बैंक द्वारा एक कम्पोजिट ऋण के रूप में साधारण ब्याज दर पर जैसा ऐसे ऋणों के लिए लागू हो स्वीकृत किया जाता है। उद्यमियों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण एक आवश्यक संघटक है। सरकार द्वारा महिला उधारकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें प्रशिक्षण और अन्य उद्यमिता विकास सहायता प्रदान की जाती है।

केवीआईसी की दो मिलियन रोजगार कार्यक्रम

केवीआईसी की ग्रामीण रोजगार सृजन स्कीम का शुभारम्भ बेरोजगार बेकलॉग में कमी करके आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा केवीआई क्षेत्र के अन्तर्गत दो मिलियन नए जॉब अवसरों के सृजन का अनुमोदन किया गया था। केवीआईसी इस कार्यक्रम को रु० 5600 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें से एक तिहाई बजटीय सहायता द्वारा और शेष ऋणों द्वारा।

Delegation of Financial powers for speedy implementation of projects

1830. PROF. RAM KAPSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had directed the Cabinet Secretary to evolve effective programme for delegation of financial powers and simplification of procedures for speedy implementation of on-going and new projects;

(b) whether any time-limit was set for the purpose and the details of the Ministries concerned with this;

(c) whether any report has been received in this regard; and

(d) if so, the broad details of the recommendations in the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (d) The Government has been concerned about the need for streamlining the expenditure sanction

system in different Ministries/ Departments. It has, therefore, been felt that adequate powers should be delegated to the Ministries for incurring expenditure within the budgeted outlays and only in case of demand for additional funds, the matter may be referred to the Ministry of Finance. The Ministry of Finance are in the process of working out the modalities so that Minstries/ Departments are enabled to implement their plan and non-plan schemes without any delay.

Criteria for approval of plan size of States

1831. SHRI MD. SALIM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total Plan size from the 1st to the 9th Five Year Plans; Plan-wise and State-wise;

(b) the Plan-wise percentage of increase in succesive Plans, State-wise;

(c) the norms/criteria adopted while approving the Plan size of States;

(d) whether allegations of discrimination against States were aired by the States; and

(e) if so, the highlights of those allegations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) The originally approved outlays for the State Plans from 1st Five Year Plan to Ninth Five Year Plan and Plan-wise percentage of increase in the successive plans is given in Annexure. [*See* Appendix 181, Annexure No. 48] (c) to (e) The Plan size of the States are decided in meetings at the level of Deputy Chairman, Planning Commssion with the Chief Ministers of the concerned State through mutual discussion keeping in view the projections of Central Asistance and State's Own Resources. The allocation of Normal Central Assistance is made on the basis of the formula approved by the National Development Council (NDC). Chief Ministers have generally been pleading for higher levels of Central Assistance.

Benefits from Insat-2D

1832. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether, after functioning of the INSAT-2D, Indian ships are likely to improve their navigational and other areas; and

(b) If so, the details of the fields likely to improve?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) INSAT-2D satellite launched in June 1997 does not carry any Navigation package. However, it carries a mobile communications transponder for use by ships and other vehicles. INSAT-2D carries 18 C & Ext-C band, 3 Ku-band, 1 S-band and 1 Mobile Satellite Service (MSS) transponder for communication.

The INSAT-2D satellite, therefore, cannot be of direct assistance to Indian ships for navigational purposes. The MSS transponder can be used for voice and data communications from and to ships equipped with appropriate moble terminals and this could be of assistance to navigation in a indirect manner.

Nuclear Thermal Rockets

1833. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Indian scientists have worked on Nuclear Thermal rockets;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by wnen India would be able to launch its own space satellites, like INSAT-2D?